RNI : UAHIN/25/A3210

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक

वर्षः 01 | अंकः 02 देहरादून, शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 | मूल्य 2 रुपये | पृष्ठः 8 | www.aawamindia.com

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं : पीएम

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हो रही चर्चा के दौरान जमकर विपक्षी दलों पर तंज कसा।

अपने चिर-परिचित अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब कुछ लोगों को लग रहा है कि यह मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है? इसका अगर विरोध किया जायेगा तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन सब साथ मिलकर चलेंगे तो किसी को भी लाभ नहीं होगा, यह लिखकर ले लो क्योंकि फिर इसका अलग पहलू हो जाता है। अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही यह पारित होगा, मैं सबका आभार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। आप ले लो क्रेडिट। जिसकी फोटो भी आप (विपक्ष) कहेंगे, हम सरकारी खर्चे से उसकी फोटो विज्ञापन में छपवा देंगे। मैं आपको सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि हम भ्रम में न रहें, हम उस अहंकार में भी न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। यह उनका हक है। हमने कई दशकों से उन्हें रोका है। आज उनका प्रायश्चित कर के उस पाप से मुक्ति पाने का मौका है। पीएम मोदी ने सभी दलों से अपील की और कहा कि इसको राजनीति के तराजू से न तौलें। हम जब भी कुछ निर्णय लेते हैं तो उसका आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी हक बनता है।

संसदीस सीटों की परिसीमन प्रक्रिया पर भी नरेंद्र मोदी मुखर होकर बोले कि जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ उस अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व है फिर चाहे

कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम एक साथ सोच सकते हैं और एक साथ निर्णय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, परिसीमन प्रक्रिया में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को भरोसा देते हुए कहा कि, अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं। अगर वादा की बात करें तो वादा करता हूं। जब नीयत साफ होती है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं होती।

देश में इस समय महिला आरक्षण विधेयक चर्चा में है। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2026 पेश किया है। इस पर दो दिन चर्चा की जा रही है और साथ ही दो और विधेयकों को पटल पर रखा गया है। इसमें एक विधेयक महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़ा है, ताकि 2029 के चुनाव से पहले ही लोकसभा का संख्याबल 543 से बढ़ाकर 850 की जा सके और महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू कर उन्हें सदन में जगह दी जा सके। लोकसभा में होने वाली इस प्रक्रिया को कुछ समय बाद राज्य की विधानसभाओं में भी दोहराया जायेगा जिससे राज्यों में सीटों को बढ़ाया जा सकेगा।

इस बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इन 3 बिलों से दक्षिण के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी जो पूरी तरह झूठ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी। अकेले तमिलनाडु में ही सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जायेगीं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अभी 28 सीटें हैं जबकि परिसीमन के बाद यहां से 42 सांसद आयेंगे। आंध्र प्रदेश में अभी 25 सीटें हैं यहां परिसीमन के बाद 38 सीटें हो जायेंगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं यहां बढ़ोत्तरी के बाद 26 सीटें हो जायेंगी। केरला में 20 की जगह 30 सांसद हो जायेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि मैं इस बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में इसे सदन में रख रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं उसके लिए मेरी कोई टिप्पणी नहीं है लेकिन वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा तो मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं।

बिल में कहां और कहां से मैं आंकड़े निकाल रहा हूं कल उन्हें बता दूंगा और गारंटी दे कि सुनेंगे वाकआउट ना कर जाये। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना करने का निर्णय ले लिया है और अगली जनगणना में जाति जनगणना ही होगी।

अभी फिहलाल घरों की गणना की जा रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। अमित शाह ने ये भी कहा कि 2029 तक जो भी चुनाव होंगे वो पुरानी व्यवस्था पर ही होंगे।

अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2027 में आप नहीं जीत रहे हो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्यो चुनाव पुरानी व्यवस्था पर होंगे। लोकतंत्र पर बोलते हुए ये भी कहा कि किसी की ताकत नहीं हैं जो लोकतंत्र को खत्म कर सके और जिसने ये कोशिश की है वो खुद खत्म हो गये हैं।

संसद में नरेंद्र मोदी का चिर-परिचित अंदाज

कुछ लोगों को लग रहा है कि यह मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है? इसका अगर विरोध किया जायेगा तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन सब साथ मिलकर चलेंगे तो किसी को भी लाभ नहीं होगा, यह लिखकर ले लो क्योंकि फिर इसका अलग पहलू हो जाता है। अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही यह पारित होगा, मैं सबका आभार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। आप ले लो क्रेडिट। जिसकी फोटो भी आप (विपक्ष) कहेंगे, हम सरकारी खर्चे से उसकी फोटो विज्ञापन में छपवा देंगे। मैं आपको सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं।

अमित शाह ने दिखाये कड़े तेवर

मैं इस बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में इसे सदन में रख रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं उसके लिए मेरी कोई टिप्पणी नहीं है लेकिन वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा तो मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं। बिल में कहां और कहां से मैं आंकड़े निकाल रहा हूं कल उन्हें बता दूंगा और गारंटी दे कि सुनेंगे वाकआउट ना कर जाये।

प्रियंका गांधी ने सरकार पर लगाये गंभीर आरोप

मौजूदा सरकार एक बार देश की आंखों में धूल झोंककर देश की अखंडता पर बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बात करके दूसरी तरफ ओबीसी महिलाओं का हक छीना जा रहा है। कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की हत्या करके अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी योजना बना रखी है यदि चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते।

फ्यूचर रेडी बने युवा, नेशन फर्स्ट को हमेशा रखें ध्यान : मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में ओहो रेडियो एवं ड्रीमर्स एड्यु हब के सौजन्य से आयोजित "राष्ट्र निर्माण उत्सव"

कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए तीन नए रेडियो चौनलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वे इस प्रेरणादायी आयोजन में उपस्थित सभी अतिथियों एवं युवा साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं तथा ओहो रेडियो के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक मजबूत, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि एक समय था जब रेडियो घरों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और इसकी उपस्थिति से अधिक उस पर प्रसारित होने वाली सूचनाएं महत्वपूर्ण होती थीं। गांवों में सीमित घरों में रेडियो होने के बावजूद लोग एकत्र होकर समाचार सुनते और गीतों का आनंद लेते थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके पास भी एक छोटा रेडियो था, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ तकनीक में परिवर्तन आया है, लेकिन रेडियो की आत्मीयता और विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा "मन की बात" कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो को पुन: मुख्यधारा में स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ओहो रेडियो भी उत्तराखंड में इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बीच उपस्थित होकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आए युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ देवभूमि उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र के पुनर्जागरण का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे और उनका आह्वान था कि लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी अनेक युवा उनके विचारों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी युवाशक्ति संगठित, आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा, समर्पण और सृजनात्मकता को राष्ट्र की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना को सशक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों-युवा, किसान, महिलाएं, श्रमिक, उद्यमी और बुद्धिजीवी-की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और यही युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले, तो भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि पुन: विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार भी युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने, कौशल विकास को प्राथमिकता देने और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज के युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में रोजगार के स्वरूप में तेजी से बदलाव आ रहा है, इसलिए युवाओं को फ्यूचर-रेडी बनाना आवश्यक है। इसी दिशा में राज्य सरकार डिमांड-बेस्ड स्किल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि देवभूमि का राष्ट्र निर्माण में योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने "स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर" के निर्माण और दून विश्वविद्यालय में "सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज" की स्थापना को इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्हें राष्ट्र का भावी प्रहरी बताया और युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि युवाशक्ति के समर्पण, नवाचार और संकल्प से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता राकेश बेदी , मेजर प्राजुक्ता देसाई, आरजे काव्या सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री ने किया मखाना की खेती का स्वयं रोपण

हरिद्वार। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र स्थित गंगदासपुर बालावाली में मणिगाछी एफपीओ द्वारा शुरू किए गए मखाना की

खेती के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं मखाना रोपण कर हरिद्वार जनपद में मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की। गौरतलब है कि बिहार की एक संस्था द्वारा उत्तराखण्ड में पहली बार हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में मखाना खेती का पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संस्था के पदाधिकारियों को इस प्रयास के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया, जो उत्तराखण्ड सहित देश के 11 राज्यों में मखाना उद्योग को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक रुपये 476 करोड़ के परिव्यय के साथ मखाना विकास हेतु केंद्र पोषित योजना संचालित की जा रही है, जिसमें अनुसंधान, गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन, कौशल विकास, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के अंतिम त्रैमास में उत्तराखण्ड को रुपये 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्र धनौरी (हरिद्वार), ढकरानी (देहरादून) एवं काशीपुर (उधमसिंहनगर) के सहयोग से किसानों को मखाना उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही प्रदर्शन प्लॉट भी स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए रुपये 143.16 लाख की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखण्ड को औद्यानिकी प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। सेब की अति सघन बागवानी के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 230 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इसके अलावा मिलेट्स, कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग नीतियां लागू की गई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से प्रदेश के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अवसर पर उद्यान विभाग से बागवानी निदेशक महेन्द्र पाल, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, संस्था के अध्यक्ष राजीव रंजन, डॉ. प्रेम कुमार, अजय पैनोली, अनुज प्रधान, दीपक सैनी, अजय शर्मा, कृष्णपाल चौहान, बाबूराम सहित बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित रहे।

बागेश्वर में 132 केवी जीआईएस उपकेन्द्र का होगा कायाकल्प

बागेश्वर। जनपद बागेश्वर में विद्युत आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु पिटकुल के 132 केवी जीआईएस उपकेन्द्र बागेश्वर के पुनरोद्धार (कायाकल्प) कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए विश्व बैंक से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मोहम्मद अफजाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने हेतु विभाग द्वारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (च्न्) का गठन कर लिया गया है। वर्तमान में टीम की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक प्रोक्योरमेंट असेसमेंट से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आगे बताया कि निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार, सीईआरसी (ब्म्त्ब्) के एक्टिवेशन के माध्यम से पुनरोद्धार कार्य को तय समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। इस परियोजना के पूर्ण होने से जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आएगा। वर्तमान विद्युत व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता ने बताया कि बागेश्वर जनपद को फिलहाल रानीखेत एवं अल्मोड़ा स्थित 132 केवी उपकेन्द्रों के माध्यम से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बढ़ती विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए फरवरी माह में रानीखेत उपकेन्द्र पर बागेश्वर के लिए 20 एमवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया गया है, जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को और अधिक मजबूती मिली है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल

बागेश्वर। जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग द्वारा जिला अस्पताल बागेश्वर में एक नए विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती की गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. कुमार आदित्य तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा डॉ. गौरव सिंह कैड़ा को उनकी पीजी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत जिला चिकित्सालय बागेश्वर में नियुक्त किया गया है। डॉ. कैड़ा पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालाखेत, बेतालघाट (जनपद नैनीताल) में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। उनकी इस नई तैनाती को राज्यपाल की ओर से सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। इस उच्च शिक्षित विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति से बागेश्वर जनपद सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर एवं विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उपचार की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आने की अपेक्षा है।

राज्य के हर स्कूल में बजेगी वॉटर बेल

ग्रीष्म ऋतु की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वॉटर बेल बजाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रत्येक छात्र-छात्राएं गर्मियों के मौसम में नियमित अंतराल पर पानी पी सकें और डिहाइड्रेशन से बचाव सुनिश्चित हो। मुख्य सचिव ने बुधवार को ग्रीष्मकाल में हीटवेव की तैयारियों को लेकर शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने विद्यालय के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने, कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन, ओआरएस एवं आवश्यक दवाओं का भंडारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को हीट वेव से बचाव सम्बन्धी व्यवहारिक जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में बढ़ते तापमान एवं संभावित हीट वेव की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को गर्मियों के मौसम में जिन भी क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो, वहां सभी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बसों, स्टेशन, बाजार में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हीट वेव की चुनौती से निपटने के लिए राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक सभी विभाग समन्वित एवं सक्रिय रूप से कार्य करें।

प्रत्येक जनपद में हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करते हुए संवेदनशील (हॉटस्पॉट) क्षेत्रों की पहचान की जाए तथा वहां विशेष निगरानी एवं राहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही 24ञ7 कंट्रोल रूम संचालित कर किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए। मुख्य सचिव ने पेयजल की उपलब्धता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैंड, पंचायत भवनों आदि पर स्वच्छ पेयजल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में जल संकट की संभावना है, वहां अग्रिम कार्ययोजना बनाकर टैंकरों की व्यवस्था, नलकूपों एवं पंपिंग सिस्टम की नियमित निगरानी तथा वैकल्पिक जल आपूर्ति व्यवस्था तैयार रखी जाए। उच्च मांग की स्थिति में आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निर्देशित किया कि सभी चिकित्सालयों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु पर्याप्त बेड, समर्पित वार्ड, आवश्यक दवाइयां, ओआरएस एवं आइस पैक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एम्बुलेंस सेवाओं को सुदृढ़ रखते हुए उनमें आइस पैक तथा ओआरएस अनिवार्य रूप से रखा जाए तथा चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ को हीट वेव प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। आमजन को हीट वेव के लक्षण, बचाव एवं प्राथमिक उपचार के सम्बन्ध में व्यापक रूप से जागरूक किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सालयों में मरीजों के बैठने के स्थान पर शेड और पंखे हों। मुख्य सचिव ने हीटवेव के दौरान श्रमिकों एवं खुले में कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि कार्य समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाए, विशेषकर दोपहर के समय भारी कार्य से बचा जाए। कार्यस्थलों पर छायादार विश्राम स्थल, आइस पैक, स्वच्छ पेयजल, ओआरएस तथा प्राथमिक उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही श्रमिकों को हीट वेव से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी आश्रय (कूलिंग स्पेस), पानी के प्याऊ/वॉटर कियोस्क स्थापित किए जाएं तथा जरूरतमंद लोगों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पार्कों को अधिक समय तक खोलने, गरीब एवं संवेदनशील वर्गों तक राहत पहुंचाने तथा पशुओं के लिए भी पानी एवं शेल्टर की समुचित व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव महोदय ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए कि बढ़ती मांग को देखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ट्रांसफार्मर एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गैस आपूर्ति प्रभावित होने के चलते किचन में विद्युत उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। सामान्यतौर पर गर्मियों में एसी, पंखे, कूलर के कारण विद्युत मांग में वृद्धि रहती है। इसलिए बिजली की मांग इस सीजन बढ़ सकती है, लिहाजा उच्च मांग के समय वैकल्पिक योजना तैयार रखते हुए आवश्यक सेवाओं पर प्रभाव न पड़ने दिया जाए। इस अवसर पर सचिव श्री दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सीसीएफ श्री सुशांत कुमार पटनायक, डॉ. पराग मधुकर धकाते, श्री सी. रविशंकर, श्री विनोद कुमार सुमन एवं श्री रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने ली शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में वनाग्नि की रोकथाम को लेकर सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि से सम्बन्धित सभी समितियों एवं स्टेकहोल्डर्स के साथ सभी आवश्यक बैठकें जनवरी माह तक अनिवार्य रूप से आयोजित कर सभी व्यवस्थाएं, फायर सीजन से पहले सुनिश्चित करवा ली जाएँ। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगे फायर हाइड्रेंट्स के लिए डेडिकेटेड प्रेशर पाइपलाइन व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पेयजल विभाग को शीघ्र प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने वन विभाग को ड्राइव चला कर सभी प्रकार के वनाग्नि की रोकथाम से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों एवं उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी लीसा डिपो में प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वन, मौसम एवं वन सर्वेक्षण संस्थान को फारेस्ट फायर के लिए भी आपदा की तर्ज पर प्रिडिक्शन मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे फारेस्ट फायर की संभावनाओं का पहले से अनुमान लगाया जा सकेगा जिससे जानमाल के नुकसान को रोकने और कम करने में सहायता मिलेगी। मुख्य सचिव ने जंगलों से पिरूल के निस्तारण और पिरुल ब्रिकेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर जोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि पिरुल ब्रिकेट को ईंधन के विकल्प के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक यूनिट लगाए जाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक ओर वनाग्नि को रोकने में सहायता मिलेगी वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक को भी सुधारने में मदद मिलेगी साथ ही इसे कार्बन क्रेडिट से भी जोड़ा जा सकता है।

जनपद में एलपीजी सिलेंडरों का सफल वितरण, आपूर्ति व्यवस्था सुचारू

बागेश्वर। जनपद बागेश्वर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का वितरण विभिन्न गैस एजेंसियों के माध्यम से सुचारू रूप से किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी जी.बी. पांडे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बुधवार को कुल 425 गैस सिलेंडरों का सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित किया गया।

वितरण के अंतर्गत इण्डेन गैस सर्विस कपकोट द्वारा कपकोट गांव, लीली, पनौरा क्षेत्र क्षेत्र में 190 सिलेंडर, इण्डेन गैस सर्विस काण्डा द्वारा भाकड़पंत, मन्तोली क्षेत्र में 100 सिलेंडर, शिखर भारत गैस सर्विस शामा द्वारा बागेश्वर बाजार क्षेत्र में 50 सिलेंडर तथा शुभम गैस एजेंसी गरुड़ द्वारा नई वस्ती, ढुंगापाटली, कांडे, नायल, सिमतोली, भिड़ी, किमोली, स्यालडोबा, गुरना क्षेत्र क्षेत्रों में 85 सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद के सभी क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति सामान्य एवं सुचारू रूप से जारी है तथा किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर गैस उपलब्ध कराने हेतु संबंधित गैस एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

राज्यपाल के समक्ष 'विधि सहयोगी' एप का प्रस्तुतीकरण

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष आज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट ने 'विधि सहयोगी' मोबाइल एप का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया गया कि 'विधि सहयोगी' एक एआई सक्षम मोबाइल एप है, जो आम लोगों को सरल भाषा में कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और विधिक सहायता तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। एप के माध्यम से उपयोगकर्ता कानूनी विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अध्ययन सामग्री हासिल कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अधिवक्ताओं से संपर्क भी कर सकेंगे। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि भविष्य में इसमें ऑनलाइन परामर्श, केस ट्रैकिंग, दस्तावेज प्रबंधन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। कुलपति ने बताया कि इसपर कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। राज्यपाल ने एप को तैयार करने वाली टीम एवं विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवाचार समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि एप में समय-समय पर आवश्यक सुधार एवं अपडेट किए जाते रहें, ताकि इसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता निरंतर बढ़ती रहे। उन्होंने इस एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी बल दिया, जिससे अधिक से अधिक आमजन इसके बारे में जान सकें और इसका लाभ उठा सकें तथा लॉन्च से पूर्व लोगों की जागरूकता हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल श्री रविनाथ रामन, विधि परामर्शी श्री कौशल किशोर शुक्ल एवं अपर सचिव श्रीमती रीना जोशी उपस्थित रहे।

लोक भवन में मनाया गया हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस

देहरादून। लोक भवन में हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में हिमाचल राज्य के देहरादून स्थित संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसमें हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सभी उपस्थित जनों को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के बीच केवल भौगोलिक निकटता ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्तर पर भी गहरा और आत्मीय संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों को 'देवभूमि' के रूप में जाना जाता है, जहां की पवित्रता, लोक परंपराएं, आस्था, सरल जीवनशैली और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना एक समान रूप से परिलक्षित होती है। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस का आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की विविधता को समझने और उसे आत्मसात करने का एक सशक्त माध्यम है। ऐसे आयोजन हमें एक-दूसरे की भाषा, वेशभूषा, खान-पान, लोक कला और परंपराओं को जानने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे राज्यों के बीच आपसी सद्भाव, संवाद को बढ़ावा मिलता है।

सम्पादकीय

केंद्र सरकार के साथ तालमेल का सुनहरा दौर

केंद्र और राज्य के संबंध अक्सर सत्ता संतुलन, विकास और राजनीतिक समीकरणों के बीच झूलते रहते हैं। दोनों जगह सरकारें एक भी हो तो जरूरी नहीं होता कि तालमेल भी एक हो लेकिन पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड के लिए परिदृश्य बदला हैं। इस बदलाव के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शानदार बॉडिंग है। ये नजदीकियां बताती हैं कि यह संबंध केवल औपचारिक नहीं, बल्कि एक कार्यशील साझेदारी का उदाहरण बनता जा रहा है। जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड का दौरा करते हैं, वे राज्य सरकार की योजनाओं की खुलकर सराहना करते हैं। बदले में, धामी सरकार भी केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करने में पंक्ति में सबसे पहले दिखाई देती है। ये केंद्र सरकार के साथ तालमेल का सुनहरा दौर है। ये डबल इंजन सरकार का भी सुनहरा दौर है।

हमें याद है कि देहरादून परेड ग्राउन्ड में एक जनसभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार ही पहाड़ में विकास कर सकती है। दो इंजन पहाड़ की चढ़ाई में थकेंगे नहीं। जनता ने उनके इस बयान को स्वीकार किया था और पहली बार इतने बंपर बहुमत की सरकार 2017 में भाजपा की बनी थी। यही सरकार मोदी-धामी की सरकार के नाम पर 2022 में रीपीट हुई। ये डबल इंजन इतना पोपुलर हुआ कि जहां-जहां भाजपा शासित सरकारें आती रही, डबल इंजन की सरकार का मुहावरा दोहराया जाता रहा लेकिन जो बॉडिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखायी देती है वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहीं बेहतर और अलग है।

इस बॉन्डिंग का सबसे बड़ा लाभ राज्य के विकास में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। चारधाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, हेमकुंड रोपवे, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और रेल कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट इसका उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी प्रशासनिक शैली तेज निर्णय लेने और कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो प्रधानमंत्री की कार्यशैली से मेल खाती है। यही कारण है कि उत्तराखंड में विकास कार्यों की गति अपेक्षाकृत तेज नजर आती है।

मोदी-धामी की यह जोड़ी भाजपा के भीतर एक स्पष्ट संदेश भी देती है कि केंद्रिय हाईकमान युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अनुभव का संतुलन बनाए रख रहा है। पुष्कर सिंह धामी अपेक्षाकृत युवा मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री का समर्थन मिलना पार्टी के भीतर उनके कद को मजबूत करता है। इसके अलावा, यह संबंध संगठनात्मक स्तर पर भी भाजपा को मजबूती देता है। चुनावी राजनीति में जब शीर्ष नेतृत्व और राज्य नेतृत्व एकजुट दिखते हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और मतदाताओं में विश्वास पैदा होता है।

ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली हो सकती है कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और नीतिन गडकरी भी एक अलग आत्मीय भाव के साथ उनसे मिलते हैं। यह आत्मीय भाव केवल व्यक्तिगत समीकरण का परिणाम नहीं है बल्कि एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। भाजपा के लिए उत्तराखंड एक संवेदनशील और रणनीतिक राज्य है। धार्मिक, पर्यटन और सैन्य दृष्टि से इसका महत्व बहुत अधिक है। ऐसे में योजनायें धरातल पर उतरती रहें, उन्हें भरपूर बजट और तेज कार्यशैली मिलती रहे जनता का विश्वास जीतना फिर मुश्किल नहीं होता है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे लोकार्पण के दौरान कहा था कि सड़कें, कोरीडोर और एक्सप्रेसवे राष्ट्र की भाग्य रेखायें होती हैं। हम एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि हर क्षेत्र में विकास ही राष्ट्र की भाग्य रेखा है। मौजूदा सरकार इन रेखाओं का विस्तार कर रही है जो उत्तराखंड के लिहाज से आवश्यक भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि उत्तराखंड केवल हिमालयी राज्य नहीं है, यह भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक चेतना का एक संवेदनशील क्षेत्र है। इस सुनहरे दौर का देवभूमि को लाभ मिलना चाहिए। पूर्ण और स्पष्ट बहुमत की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, एक विजन रखते हैं, संवेदनशील है और केंद्र सरकार उनके हर फैसले में उनके साथ खड़ी है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि उत्तराखंड के विकास में ये दौर मील का पत्थर साबित होगा।

मौ. वसी जैदी
सम्पादक

महिला आरक्षण: समान प्रतिनिधित्व से वास्तविक सशक्तिकरण तक

सौलत जबी, वरिष्ठ पत्रकार

आज जब देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है तो ये जरूरी हो जाता है कि विकास की इस यात्रा में आधी आबादी की भी बराबर भागीदारी हो। ये जरूरी हो जाता है कि समानता, न्याय और समावेश की बातें किताबी ना हो धरातल पर भी दिखायी दे। महिला आरक्षण संशोधन बिल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बेहतर है वो और बेहतर हो सकता है और भारत में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां ये कदम ना सिर्फ आवश्यक है बल्कि जिम्मेदारी भी है। राजनीति एक ऐसा अध्याय है जहां से समाज से चलता है, लोकतंत्र चलता है। इस अध्याय में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सभ्य और सुरक्षित समाज की परिकल्पना की दिशा तय करेगी। हमारा संविधान समानता के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह समानता अभी तक अधूरी है। ऐसे में महिला आरक्षण की बात करना एक नीतिगत फैसला नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक ऐतिहासिक पहल का पहला कदम है।

16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। दरअसल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल पास तो तीन साल पहले ही हो गया था लेकिन इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने के लिए और संख्या को 33 फीसदी करने के लिए संशोधित बिल लाया जा रहा है।

ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही है। स्वतंत्रता के बाद संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में वे पीछे ही रहीं। 1992-93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया गया। इस कदम ने जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया और लाखों महिलाएं पहली बार सत्ता और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनीं। यह प्रयोग काफी सफल रहा और इसने यह सिद्ध किया कि यदि अवसर मिले, तो महिलाएं न केवल भागीदारी कर सकती हैं, बल्कि प्रभावी नेतृत्व भी दे सकती हैं। अब सवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत का है। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे कई वर्षों से लंबित रखा गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी का मांग होती रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद, सामाजिक समीकरणों की जटिलता और पिछड़े वर्ग पर एक सकारात्मक बहस हो सकती है पर शायद ये हर कोई चाहेगा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े।

हाल के वर्षों में इस विधेयक को लेकर नई पहल और राजनीतिक इच्छाशक्ति देखने को मिली है, महिलायें भी अपनी भागीदारी की भूमिका के दायरे को बढ़ा रही हैं। जागरूक हो रही हैं। मुखर हो रही हैं। एक दृष्टिकोण तय रही हैं। एक नजरिया बना रही है और ये अच्छे संकेत हैं। हाल ही के वर्षों में जब प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं तो देशभर में महिला वर्ग ने उनका समर्थन किया था। दरअसल लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का सीधा संबंध नीति निर्माण से होता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब किसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो उसके मुद्दे भी प्राथमिकता में नहीं आते। भारत की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है, अब निर्णय सकारात्मक हो या इग्नोर किया जाये पर महिलाओं की आवाज निर्णय प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल नहीं है।

आज जरूरत है कि महिला आरक्षण के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाये कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े और वे अपने अनुभवों और दृष्टिकोण के आधार पर नीतियों को प्रभावित कर सकें। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, लैंगिक हिंसा, और रोजगार जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और प्रभावी नीतियां बने। ये बदलाव राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित ना रहे बल्कि इसका व्यापक सामाजिक असर भी हो। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में दिखाई दें, तो समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आये। ये बदलाव लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। परिवारों में बेटियों की शिक्षा और करियर को लेकर सोच बदले। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करे।

लोग कहते हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित रहती है। जिसे "प्रॉक्सी राजनीति" कहते हैं। यानि महिलाएं केवल नाममात्र की प्रतिनिधि हों और वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य लें। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसे पूरी तरह नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है लेकिन अब वक्त बदला है। महिलायें बढ़-चढ़कर सकारात्मक भूमिकायें निभा रही हैं और बिना किसी सकारात्मक हस्तक्षेप के महिलाओं को समान अवसर मिल पाना कठिन होता है। ये आरक्षण एक प्रारंभिक कदम है, जो समय के साथ सामाजिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम हर उस पहल का समर्थन करें जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती हों क्योकि जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी समाज और राष्ट्र भी सशक्त होगा।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राहम्णवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,
समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331
हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।
facebook: www.facebook.com/indiaaawam, youtube:www.youtube.com/@aawamindia,
X:www.x.com/aawamindia, Instagram:https://instagram.com/aawamindia

बीमार स्वास्थ्य सेवाओं के इलाज में जुटे सुबोध उनियाल !

देहरादून : विषम भौगोलिक स्वरूप वाले उत्तराखंड में यदि पलायन के कारण तलाशे जाते हैं तो लचर स्वास्थ्य सेवायें आज भी सबसे ऊपर आती हैं। ये खूबसूरत

पहाड़ी राज्य की कड़वी सच्चाई है कि दूरस्थ गांवों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं किसी सपने की तरह हैं। इन गुजरे हुए 25 सालों में ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। हालात पहले के मुकाबले बेहतर तो हुए हैं लेकिन इतने बेहतर नहीं हो सके जिसकी आवश्यकता थी। आज भी कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जमीनी स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों और जरूरी उपकरणों की भारी कमी है। आज भी कई क्षेत्रों में मरीजों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए 50-100 किलोमीटर दूर जिला अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और जिला अस्पताल भी अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। नये स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल इन पुरानी स्वास्थ्य सेवाओं की बीमारियों का इलाज तलाश कर रहे हैं लेकिन क्या ये इतना आसान होगा।

पुष्कर सिंह धामी 2.0 की सरकार में 4 वर्ष के बाद इस चुनावी वर्ष में एक बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल करते हुए डॉ. धन सिंह रावत की जगह सुबोध उनियाल को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य स्वयं में ऐसा विभाग है जहां अवसर से ज्यादा चुनौतियां होती हैं। सबसे ज्यादा प्रश्नचिन्ह होते हैं और सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है। जहां प्रशंसा के अवसर कम और आलोचना की उम्मीदें ज्यादा होती हैं। सुबोध उनियाल इन चुनौतियों को समझते होंगे। वो स्वयं पहाड़ की पृष्ठभूमि से निकले एक अनुभवी नेता हैं। वो जमीनी स्तर को समझ सकते हैं और यही एक बड़ी वजह भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा मिलने के बाद वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल और प्रदेश के सबसे बड़े हायर सेंटर तक खुद मॉनीटरिंग कर रहे हैं और अपने शुरूआती फैसलों में सुबोध उनियाल ने स्पष्ट कर दिया है कि उन डॉक्टरों का अफसर अच्छे से इलाज करे जो बेवजह मरीज को रेफर करते हैं और बाहर से महंगी दवाइयां लिखते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज का इलाज नहीं रूकना चाहिए। यदि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है तो निजी अस्पतालों से भी संबधित स्पेशलिस्ट डॉक्टरों

को बुलाया जायेगा और ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जायेगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी पर ये एक अच्छा कदम साबित होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी चिंतन किया कि कैसे इमरजेंसी सेवाओं को तेज और बेहतर बनाया जा सकता हैं ये पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी जरूरत हैं। यदि दुर्गम क्षेत्रों में समय रहते इलाज मिलना शुरू हो जाये तो पहाड़ की मूलभूत संरचना और उद्देश्य में ये मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि ये शुरूआती कदम हैं लेकिन अभी चुनौतियां अपार हैं।

केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अहम योजनाओं का संचालन किया है जैसे आयुष्मान भारत योजना, टेलीमेडिसिन सेवाएं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, 108 योजना, ई-स्वास्थ्य धाम योजना, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच व दवा योजना। ऐसे और भी कई योजनायें हैं लेकिन पहाड़ में जागरूकता और प्रचार की कमी के कारण इनका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहाड़ में प्राकृतिक विषम भौगोलिक परिस्थितियां एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण वजह हो सकती हैं लेकिन अन्य कुछ और चुनौतियां भी निदान की राह देख रही हैं। जैसे कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पहाड़ में तैनाती से बचते हैं क्योंकि वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मैदानी इलाकों में तो निजी अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का निवेश लगभग ना के बराबर है। टेलीमेडिसिन के लिए दुरस्थ क्षेत्रों ना पर्याप्त जागरूकता है और ना पर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी नियमित रूप से हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पातीं हैं। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को डोली या निजी वाहनों के सहारे अस्पताल पहुंचाया जाता है, जो कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। आज भी बड़ी मात्रा में नवजात बच्चों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के प्रयासों के बावजूद, पोषण की कमी है। आज भी कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पाया है। कई जगह अस्पताल तो बने हैं लेकिन अस्पतालों में आधुनिक उपकरण और पर्याप्त स्टाफ की कमी महसूस होती है। धामी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल को इन चुनौतियों से लड़ना है। गंभीर और कठिन फैसले लेने हैं। बजट की पारदर्शिता और सेवाओं की उपलब्धता के लिए स्वयं जमीनी स्तर पर उतरना है जैसा कि नये स्वास्थ्य मंत्री कर भी रहे हैं। क्योंकि देवभूमि के लोगों को भी उतनी ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलने का हक है जितनी देश के अन्य हिस्सों में उपलब्ध हैं। तभी उत्तराखंड का विकास वास्तव में संतुलित और समावेशी कहलायेगा।

डॉक्टरों को पहाड़ भेजे जाने का मांगा विकल्प

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर पहले चरण में स्वेच्छा से डॉक्टरों से विकल्प मांगे जा रहे हैं जो पहाड़ में सेवायें देना चाहते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर मैदान के मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि इसके लिए एक योजना यू कोट वी पे पहले से ही संचालित की जा रही है जिसे अब और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना में डॉक्टर द्वारा प्रस्तावित वेतन को सरकार

देने का प्रयास करती है। इस योजना में कई डॉक्टर शामिल किये जा रहे हैं।

दून अस्पताल में 6 नई स्वास्थ्य सेवाओं से आसान होगा इलाज

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून अस्पताल में 6 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया हैं। जिसमें आक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर, हर मंजिल पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्पोर्टस इंजरी क्लीनिक, पैथोलॉजी विभाग मे सिक्सपैक्स मशीन, हैल्थ पैकेज जांच युनिट और पांच एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बनाये गये हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इन सेवाओं से दून अस्पताल आने वाले मरीजो को राहत और आसानी होगी। मरीजों को अपना इलाज और जांच कराने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ये हमारी प्राथमिकता है कि हम प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ पहुंचाये। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे पास शासन और विभाग में काबिल अफसर और अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो निजी क्षेत्रों से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सहायता ली जायेगी लेकिन सरकार का प्रयास होगा कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर और आसान इलाज मिले। हमारा उद्देश्य और प्राथमिकता है कि हम स्वस्थ उत्तराखंड बनाकर स्वस्थ भारत बनाने की संकल्पना को साकार करे।

अश्व क्षेत्र को मिलेगी नई उड़ान: राज्य सरकार और संस्थाओं के बीच होगा करार

देहरादून। देश के अश्व क्षेत्र (इक्वाइन सेक्टर) के इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। इस दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए, राज्य की पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने संबंधित संस्थाओं के साथ श्सहमति पत्रश पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। वे एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में श्द इक्वाइन कलेक्टिवश द्वारा आयोजित श्द इक्वेस्ट्रियन फोरम 2026श के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थीं। विरासत और आधुनिकता का संगम इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य के विपणन एवं शिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल उपस्थित थे। साथ ही, श्द इक्वाइन कलेक्टिवश की संस्थापिका गायत्री कराड, एमआईटी-डब्ल्यूपीयू के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राहुल विश्वनाथ कराड, कार्यकारी निदेशक डॉ. अदिति राहुल कराड, नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया के डॉ. एफ. एफ. वाडिया और जयपाल सिंह रावल भी मंच पर आसीन रहे। मंत्री पंकजा मुंडे ने जोर देकर कहा कि अश्व क्षेत्र केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं छिपी हैं। उन्होंने कहा, ष्नए विचार हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन उनमें बदलाव लाने की असीम शक्ति होती है। अश्व क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है।ष असंगठित से संगठित होने की ओर संस्थापिका गायत्री कराड ने वैश्विक परिदृश्य को रेखांकित करते हुए बताया कि भारत का अश्व क्षेत्र +300 बिलियन के वैश्विक इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अब भी असंगठित है। उन्होंने कहा, ष्इस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति के लिए औपचारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन का अभाव है। हम इस फोरम के माध्यम से एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जो कौशल विकास और दीर्घकालिक करियर के अवसर प्रदान करेगा।मंत्री जयकुमार रावल ने इंसान और घोड़ों के भावनात्मक संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की इस समृद्ध विरासत को सहेजते हुए इसके आधुनिकीकरण (अश्व पर्यटन और पशु चिकित्सा) पर ध्यान देना आवश्यक है। वहीं, डॉ. राहुल कराड ने शिक्षा, खेल विज्ञान और सरकार के बीच त्रिकोणीय सहयोग को इस क्षेत्र की मजबूती का आधार बताया। श्वेत पत्र और भविष्य का रोडमैप उद्घाटन सत्र के बाद श्नीति और प्रशासनश पर एक गहन परिचर्चा हुई, जिसका संचालन वरिष्ठ पत्रकार सायरस मदन ने किया। इस मंथन के आधार पर श्द इक्वाइन कलेक्टिवश जल्द ही एक श्श्वेत पत्रश जारी करेगा, जिसमें प्रमुख अंतर्दृष्टि और रणनीतिक सिफारिशें शामिल होंगी।

अब दिल्ली दूर नहीं

एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर राष्ट्र की भाग्य रेखाएं : पीएम मोदी

देहरादून। सर पर ब्रहमकमल टोपी, भाषा में गढ़वाली-कुमाऊंनी के छोटे-छोटे वाक्य, वही चिर-परिचित अंदाज, वहीं देवभूमि

सीएम पुष्कर सिंह धामी को उर्जा और शक्ति दे गये पीएम मोदी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा खासा सुकून और उर्जा देने वाला था। हमेशा मंच पर दोनों का एक साथ आत्मीय लगाव देखने को मिलता हैं। जिस प्रेम और भाव के साथ नरेंद्र मोदी सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलते हैं वो किसी अन्य के साथ देखने को नहीं मिलता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के लिए लोकप्रिय, कर्मठ और युवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जो उनके लिए किसी उर्जा से कम नहीं है। सीएम धामी का पीएम के लिए तोहफा में हमेशा एक संदेशवाहक की भूमिका में होता है। इस बार मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को नंदा राजजात पर आधारित स्मृति चिह्न भेंट किया है, जिसमें मां नंदा की डोली, और अगुवाई करते खाडू के साथ स्थानीय लोगों का सुंदर चित्रण किया गया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड के लिए ऊर्जा और विकास की नई सौगात लेकर आता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने के लिए विकास और विरासत की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम रहा है और 2022 की तरह देव व वीरभूमि में 2027 में भाजपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत ने आधारभूत संरचना, अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी का तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक बताया और सभी का उत्साहवर्धन किया था। प्रधानमंत्री ने सीमांत गांव माणा में आकर उसे देश का अंतिम नहीं प्रथम गांव घोषित किया था। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में पीएम ने ही वेड इन उत्तराखंड का संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश की यात्रा करके इस तीर्थ को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई और राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन से देवभूमि को खेलभूमि के रूप पहचान दिलाई। उन्होंने हर्षिल मुखबा से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया था। सीएम ने कहा आज पूरी रफ्तार के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और नवाचार में भी भारत कीर्तिमान बना रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़ी बातें –

– दून पर मां डाट काली की कृपा और आशीर्वाद है। मैं भी उत्तराखंड से आज नई ऊर्जा और नई प्रेरणा लेकर जाऊंगा।

– बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अचानक निकला था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और मुझे खुशी है कि युवाओं की ऊर्जा से प्रदेश विकास के नया आयाम छू रहा है।

– देश का संविधान गरीबों वंचितों, शोषितों को न्याय पूर्ण व्यवस्था के लिए है और बाबा साहब औद्योगिकरण की वकालत करते थे।

– हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथ की रेखाएं देखकर भविष्य बता देते हैं इसे वास्तविक जीवन से जोड़कर देखूं, तो राष्ट्र का भाग्य हमारी सड़कें होती हैं।

– यूसीसी से उत्तराखंड ने देश को नया रास्ता दिखाया है।

– इस एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के पर्यटन को खास फायदा मिलने जा रहा है और देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम के लिए यह सबसे प्रमुख होगा।

– उत्तराखंड को बारामासी पर्यटन की जरूरत है और यहां ग्रीष्मकालीन ही नहीं शीतकालीन यात्रा भी पर्यटन एक नया आयाम देगी।

– डबल इंजन सरकार द्वारा प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी के आधार पर विकास किया जा रहा है।

– हम यहां आये तो तीर्थस्थलों को स्वच्छ और सुंदर रखें और यहां कूड़ा ना फैलाएं।

– अगले साल कुंभ होगा और हमें इसे दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है।

– प्रदेश में नंदा देवी राजजात होगी और यह हमारी आस्था का केंद्र है।

– देश में चार दशक के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन बिल पास किया था और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का हक लागू करने में देरी नहीं होनी चाहिए।

– देवभूमि में गढ़ी कैंट, शहीद जसवंत सिंह रावत के शौर्य को देश कभी भुला नहीं सकता है। हमनें वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से करीब सवा लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

से पुराना लगाव, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आत्मीय भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से देहरादून को करीब करने आये थे पर साथ में लोगों का दिल जीतकर चले गये। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है लेकिन उनके दौरे पर हर बार एक नई उर्जा और उत्साह दिखायी देता है। उनके भाषण में हर बार बाबा केदार, सीमांत क्षेत्र की चिंता और प्रगति का नया खाका जरूर होता है। इस बार फिर प्रधानमंत्री ने प्रगति का नया खाका खींचा है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ये हाईवे, ये सड़कें, ये एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं हैं, ये भविष्य की सूरत बदल देंगे। ये भाग्य रेखाए आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी हैं और ये मोदी की भी गारंटी हैं।

दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेशपुर सहारनपुर में उतरकर उत्तर प्रदेश में रोड शो किया और वन्यजीव कोरीडोर का अवलोकन किया और फिर पीएम मोदी ने मां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देहरादून में 12 किमी का रोड शो किया।

इसके बाद गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह सेना मैदान में पहुंचकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और फिर बटन दबाकर देश को 213 किमी के 11,963 करोड़ की लागत से तैयार हुए दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात प्रदान की। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम के साथ मंच पर ही मौजूद थे, जबकि गणेशपुर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वर्चुअल माध्यम से उनसे जुड़े थे। इस कोरीडोर के लोकार्पण के बाद इन तीन राज्यों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है।

शेष पृष्ठ८ पर

सुरों की मल्लिका आशा जी को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा में कहानी, अभिनय, निर्देशन, गीत, संगीत सबसे महत्वपूर्ण अंग है फिर भी जो भाव गायक और गायिका अपने अंदाज या यूं कहिए कि अभिनेता, गीतकार और संगीतकार, निर्माता, निर्देशक सभी की मांगों को समायोजित कर पूरा करता है वो गायक या गायिका ही होते हैं।

आप अपनी पसंद की किसी भी फिल्म को दस या बीस बार देख सकते हैं पर गीतों को सैकड़ों या हजार बार सुनने के बाद भी फिर से सुनने पर पहली बार से भी ज्यादा ध्यान या यूं कहिए उसमें डूब कर सुन सकते हैं। आज आशा जी के भी चले जाने के बाद यूं लगता है कि सिनेमा के सबसे स्वर्णिम संगीत काल की सबसे प्रमुख कड़ी का आखिरी रत्न भी चला गया। सबसे पहले मुकेश जी फिर रफी साहब फिर किशोर दा फिर लता जी और अब अंतत: आशा जी भी बिदा हो गयी। मेरे लिए वर्सेटाइल होने का आइडियल आइकन आशा जी ही हैं। हावड़ा ब्रिज के आइए मेहरबान और चलती का नाम गाड़ी का हाल कैसा है जनाब का, मेरा साया का झुमका गिरा रे, तीसरी कसम का पान खाये सैयां हमार जैसा चुलबुलापन,बंदिनी के अब के बरस भेज भैया को बाबुल जैसा आंखों को नम कर देने वाला भावपूर्ण, सलोना सा सजन जैसा क्लासिक, पिया तू अब तो आजा, मेरा नाम है शबनम जैसा कैब्रे, उमराव जान के यादगार और सहेज कर रखने लायक गीत और इजाजत के मेरा कुछ सामान जैसा प्रयोगात्मक अनगिनत गीतों का विविधताओं से भरा जो सागर आशा जी हमें सौंप गई है वो हमेशा उनको हमारे दिलों में बसाए रखेगा। "वर्सटाइल" शब्द आशा भोंसले के लिए एक सामान्य विशेषण बन गया जो पूरी जिंदगी उनके साथ रहा। श्लताश से जब भी उनकी तुलना की गई तो उनका अद्भभुत वैविध्य उनके पक्ष मे गया। श्लताश की विराट स्वीकार्यता के आगे दूसरी गायिकाओ को जमने का अवसर दशकों तक नही मिला परन्तु आशा भोंसले अपवाद के रूप में टिकी रही। लता की आवाज शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक मानी गई तो वहीं आशा ने अपनी आवाज में जीवन के तमाम धूसर रंग समेट लिए-शरारत, चंचलता, पीड़ा, नशा, और एक गहरी, सांस लेती हुई कामना। लता जैसे पवित्र, सधे हुए गाने उनके भी भतेरे है पर उनकी पहचान इन दुसरे रंग के गानो को लेकर ज्यादा हुई जिसमे शायद वे ही सिद्धहस्त थे।

उनका करियर गीतों की रंग-बिरंगी माला की तरह रहा है। 'अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना' और 'हाल कैसा है जनाब का' मे किशोर वय की एक शरारत और चंचलता है जो आशा ही ला सकती थी। आप देखेंगे कि किशोर तो हमेशा से खिलदंड थे, 'अच्छा जी मैं हारी' मे रफी किशोर और आशा से ही प्रेरित होकर अपनी चंचलता की शुरूआत में थे।

'पिया तू अब तो आजा' गाने में उनकी आवाज जिस तरह से उन्मुक्त और चुलबुली है, वह हिंदी सिनेमा में स्त्री कामुकता के सबसे जीवंत स्वरूपों में से एक है। वही 'इन आंखो की मस्ती' और 'अंबर की इक पाक सुराही' मे वही आवाज एक ठहरी हुई उदासी और नजाकत में ढल जाती है जैसे हर शब्द के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी हो। गुलजार की फिल्म ''नमकीन'' का गाना ''फिर से अइयो बदरा बिदेशी'' में उनका स्वर दु:ख में भीगा, तपा और एकदम सधा हुआ स्वर हैं। 'दम मारो दम' में वह एक विद्रोही युवा पीढ़ी की आवाज बनती हैं, तो 'मेरा कुछ सामान' में वही स्वर स्मृतियों के धुंधले कोनों में रखे एहसासों को छूता है। कोई बिछड़े की याद मे बिलखता आकुल मन। यह वही लचीलापन है जिसने ताउम्र आशा भोंसले को प्रासंगिक रखा। हर दौर, हर संगीतकार और हर भाव के साथ सहज और सुटेबल बनाया। उन्होंने हर रंग में गाने गाये और सब में अपना श्रेष्ठ दिया।

लेकिन आशा भोंसले का आशा भोंसले होना दुनिया ने तब जाना जब संगीत की दुनिया बदल रही थी। डिजिटल ध्वनियाँ पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा को पीछे छोड़ रही थीं। इस दौर में रहमान के साथ उनका संगम एक चमत्कार की तरह सामने आया। 'रंगीला' के गाने 'तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना' में उनकी आवाज अचानक युवा हो उठती है। इतनी ताजा कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह वही गायिका है, जिसने दशकों पहले "आजा आजा" गाया था। रहमान की एक और फिल्म श्कभी ना कभीश के गाने श्मेरे दिल का वो शहजादाश में तो आशा भोंसले जैसे तूफान बनकर सामने आई। रहमान की तकनीक की समझ ने हम जैसे संगीत-रसिको को यह निर्मल सुख दिया और फिर 'जानम समझा करो' में उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक नए पॉप अवतार में ढाल लिया। यह सिर्फ एक एल्बम नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि आशा भोंसले हमेशा थी, हैं और आगे भी हमेशा रहेगी, हर दौर मे अपना नया अपडेट वर्जन लाकर। इसी दौर में संदीप चौटा का श्कमबख्त इश्कश और अदनाम शमी ने ''लकी'' फिल्म में ''लकी लिप्स'' गवाया जिसमे उनकी आवाज की गूंज अपनी उम्र के अनुसार अद्भभुत ही थी। दरअसल, आशा भोंसले की वर्सटिलिटी केवल अलग-अलग तरह के गाने गाने में नहीं है। यह उस समझ में है, जिससे वह हर गीत के चरित्र को पकड़ लेती हैं। वह सिर्फ सुर नहीं लगातीं, वह उस स्त्री को जीती हैं, जो उस गीत में है। कभी वह शहर की बेपरवाह लड़की होती हैं, कभी कोठे की तवायफ, कभी प्रेम में डूबी स्त्री, और कभी अपने अतीत से जूझती

एक अकेली आत्मा। शायद इसी कारण, आशा भोंसले को सुनना सिर्फ गाने सुनना नहीं है। यह समय के अलग-अलग टुकड़ों में बिखरी हुई जिंदगियों को महसूस करना है।

उनके गीत हमें यह याद दिलाते हैं कि एक ही आवाज में कितनी जिंदगियाँ, कितने घर बस सकते हैं। बस शर्त यह है कि वह आवाज आशा भोंसले जैसी हो। किसी बड़े बरगद के नीचे किसी पेड़ का पनपना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। पर जीवन में बहुत बार जिद, हुनर और मेहनत के दम पर जादू घट जाया करता है। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की सबसे दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले की। दोनों बहनों ने लगभग आध ी सदी तक सिनेमा पर राज किया। आज आशा ताई भी हमारे बीच नहीं रहीं पर उनके मधुर कंठ से निकलती स्वर धारा सदा ही हमारे साथ रहेगी। उनके गाए न जाने कितने ही मधुर गीत मनमोह लेते हैं। मैंने बचपन में ''उड़े जब-जब जुल्फें तेरी'' खूब सुना आज भी पसंदीदा गानों में से है। फिर उमराव जान में उनकी गायकी तो है ही तारीफ के काबिल। उनका जाना निश्चित ही हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है।

तमिल भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थाई किझावी

नई दिल्ली। थाई किझावी एक 2026 भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शिवकुमार मुरुगेसन ने लिखा और निर्देशित किया है। सुधन सुंदरम और शिवकार्तिकेयन द्वारा निर्मित, फिल्म में सिंगमपुली, अरुलडोस, मुनीशकांत, बाला सरवनन और इलावरसु के साथ राडिका सरथकुमार मुख्य भूमिका में। थाई किझावी को आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता के साथ 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। मदुरई के कडुपट्टी गांव में एक वृद्ध साहूकार पावुनुथायी अपनी बेटी सुरुली और पोते के साथ रहती हैं। गांववाले उनसे डरते हैं, जबकि परिवार के लोग उनका सम्मान करते हैं। एक दिन वह बीमार पड़ जाती हैं और मृत्यु शय्या पर आ जाती हैं। यह खबर उनके तीन अलग रह रहे बेटों, करुमथुर में साउंड टेक्नीशियन उप्पिलियन, वाडीपट्टी में ऑटो चालक विजयन और उसिलामपट्टी में फूल विक्रेता सेल्वम तक पहुंचती है, जो उनके घर आते हैं। सुरुली के अलग रह रहे पति रूबा इडली भी उनके घर आते हैं। तीनों की नजर पावुनुथायी की संपत्ति में अपने-अपने हिस्से पर है। जैसे ही गांव पावुनुथायी की आसन्न मृत्यु की तैयारी में जुटता है, गोल्ड कुमार नाम का एक जौहरी वहां आता है और उसके बेटों

को लगभग 160 सोने के आभूषणों के बारे में बताता है जो उसने अपनी बचत को चिट फंड में निवेश करके उससे खरीदे थे। रूबा इडली की जानकारी के बिना आभूषणों को छिपाने के स्थान का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसके तीनों बेटों को अब एक साथी ग्रामीण पेनीकुइक की मदद से पावुनुथायी को जीवित रखने का उपाय खोजना होगा। 24 दिसंबर 2025 को, शिवकार्तिकेयन की कंपनी शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस ने घोषणा की कि वे फिल्म थाई किझावी के लिए सुधन सुंदरम के बैनर पैशन स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाएंगे। इस फिल्म का निर्देशन नवोदित निर्देशक शिवकुमार मुरुगेसन कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले कदैसी विवसाय (2022) और आन पावम पोलथथु (2025) में सहायक निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में काम किया था , और इसमें राधिका सरथकुमार मुख्य अभिनेत्री के रूप में होंगी। तकनीकी टीम में संगीतकार निवास के. प्रसन्ना , छायाकार विवेक विजयकुमार और संपादक सैन लोकेश शामिल हैं। चूंकि कहानी मदुरै में है , इसलिए कुछ अभिनेताओं ने मदुरै की बोली में बोलने का प्रशिक्षण लिया। इस फिल्म का संगीत निवास के. प्रसन्ना ने तैयार किया है। शिवकार्तिकेयन द्वारा गाया गया पहला एकल ष्थाई किझावी वराष् 5 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। सुबलाहशिनी और एलेक्स सैमुअल जेनिटो द्वारा गाया गया दूसरा एकल ष्मैटिकिटन माइनरकुंजू ष् 21 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। इसके अलावा 2000 की फिल्म तेनाली के ष्इंजेरुंगोष , ष्एंजेयुम एप्पोथमष् गाने भी शामिल हैं। 1980 की फिल्म निनैथले इनिक्कम , 2011 की फिल्म 7 ओउम अरिवु से ष्थेलेलामाष् , 2000 की फिल्म कुशी से ष्मेघम करुक्कुथु ष्, 2004 की फिल्म विरुमांडी से ष्माडा विलक्कएष् , 2013 की फिल्म विश्वरूपम से ष्यारेंडु थेरिगिरथाष्, 2013 की फिल्म विश्वरूपम से षविक्रम विक्रमष् 1986 की फिल्म विक्रम 2004 की फिल्म विरुमांडी से ष्करबाग्रहम वितु सामी वेलियेरथु ष् और 1974 की फिल्म अवल ओरु थोडर कथाई से ष्कदावुल अमैथा वैथा मेदाईष् को मूल संगीतकारों को श्रेय देते हुए फिल्म में पुन: उपयोग किया गया है।

थाई किझावी फिल्म साउथ की चार पांच भाषाओं के साथ हिंदी में भी वीडियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। अगर आपका आजकल की उबाऊ, पकाऊ और भारी भरकम दिमाग पर जोर डालने वाली फिल्मों से अलग कुछ देखने का मन है तो यह फिल्म देखीये, पृष्ठभूमि दक्षिण भारत के किसी गांव की है गांव वाले सारे अनपढ़ होते हुए भी फिल्मों के दीवाने हैं कमल हसन और रजनीकांत तथा श्रुति उनके आदर्श हैं और बच्चों के नाम भी इन्हीं के नाम पर रखे हुए हैं। इसी गांव में एक गांव में जीने मरने और अन्य अवसरों पर डीजे तो नहीं एमप्लीफायर पर गीत संगीत बजाने वाले भी है ।जिसको भी हर अवसर पर इसी मामले का सामना करना होता है कमल हासन के गीत बजाया जाए या रजनीकांत के। खैर यही एक दबंग औरत भी रहती है जो कि शरीर से ही नहीं चेहरे और चाल ढाल और से भी दबंग है। इसने करीबन सारे गांव वालों को ब्याज पर पैसे दे रखे हैं जो ब्याज के साथ-साथ सुविधा शुल्क लेती है ,सब्जियां उठा लेने मीट उठा लेना आदि इनका उसका काम है । इसने जिस जिस को ब्याज पर पैसे दे रखे हैं उन सब की पास बुक बना रखी है और वह पासबुक के लेकर गांव में निकलती है तो पहले ही बच्चे गांव भर में चिल्ला कर दौड़ने लगते हैं कि थाई आ रही है वसूली करने सारे गांव वाले अपना काम छोड़-छाड़ के घर में किवाड़ बंद करके दुबक जाते हैं , जैसे की फिल्म शोले में गब्बर सिंह आता था।इसका भरा पूरा परिवार है बेटियां, दामाद, पोते पोतियो भी है बेटे भी है बहुएं तो है ही। गांव वालों के साथ सारे घरवाले भी इससे त्रस्त है, और वह रोज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं की थाई मर जाए। वह जब भी घर से निकलती है बच्चे उसके सारे गांव में मुनादी लगा देते हैं थाई आ रही है जैसे गांव में डाकू घुस आए हो ऐसा माहौल गांव भर में हो जाता है।

अचानक एक दिन थाई की तबीयत खराब होती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है वह सिर्फ हाथों को घुमा कर इशारे कर रही है तथा बिस्तर पर पड़ी हुई है।

पृष्ठ 6 का शेष

एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर राष्ट्र की भाग्य रेखाएं.....

दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर काम जारी है। एक

अपने संबोधन में कहा कि ये कॉरिडोर नए कारोबार के आधार बनते हैं। इस कॉरिडोर से पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। इससे पहला फायदा तो ये है कि समय की बचत होगी और आना-जाना सस्ता और तेज होगा। इससे पेट्रोल-डीजल कम खर्च होगा। दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का भी होने जा रहा है। अब इसके निर्माण में 12 हजार करोड़ खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम भी मिला। साथ ही इंजीनियर व अन्य क्षेत्रों में भी काम के अवसर पैदा हुए। किसानों, पशुपालकों की अब तेज गति से बड़ी मंडी, बड़े बाजारों तक पहुंच आसान

होगी। इससे उत्तराखंड के पर्यटन को भी बड़ा फायदा होगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम यात्रा का यह प्रमुख मार्ग बन जायेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि इस बीते एक दशक से हमारी सरकार राष्ट्र की विकास रेखाओं पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। 2014 से पहले ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालभर में पूरे देश में दो लाख करोड़ रुपये भी खर्च नहीं होते थे लेकिन आज यह खर्च 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। देवभूमि उत्तराखंड में ही सवा दो समय ऐसा भी था कि उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थीं लेकिन आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़े थे वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम महामार्ग परियोजना, रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब का रोपवे, विकास की ये रेखाएं जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही हैं।

इन भाग्य रेखाओं पर पीएम ने कहा कि भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, इसके लिए अक्सर लोग हाथ की रेखाएं दिखाया करते हैं। मैं इस विज्ञान को तो नहीं जानता हूं लेकिन कहते हैं कि ये भी एक शास्त्र है। अगर इसी संदर्भ को मैं राष्ट्र जीवन से जोड़कर देखूं तो राष्ट्र की भाग्य रेखाएं हमारी सड़कें होती हैं। हमारे हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, वाटरवे ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं हैं। बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये रेखाएं सिर्फ आज की सुविधा ही नहीं है बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी हैं और ये मोदी की भी गारंटी हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जिस रफ्तार से काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ। मेरठ में भी मेट्रो सेवा शुरू हो गयी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ है। आज देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस वे भी शुरू हो रहा है। इतने छोटे क्षेत्र में इतने कम समय में ये सब हो रहा है। आप कल्पना कीजिए देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, वह अभूतपूर्व है। आज दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बंगलूरू-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये सब प्रगति के नए द्वार हैं, गेटवे हैं, डोर हैं। इनसे उम्मीदों की डोर जुड़ी हुई है।पीएम मोदी ने ये भी कहा कि बाबा साहेब डॉ.भीमराव आंबेडकर भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वकालत किया करते थे। आप के बीच आने से पहले मुझे मां डाट काली के दर्शन का सौभाग्य मिला। देहरादून शहर पर उनकी बड़ी कृपा होती है। दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में मां डाट काली का आशीर्वाद ही बड़ी शक्ति है।

यूटीआई मिड कैप फंड - मिड कैप के सुनहरे अवसरों से दीर्घकालिक लाभ उठाएं

देहरादून। जैसे इंसानों का जीवन अलग-अलग चरणों में चलता है, वैसे ही कंपनियां भी समय के साथ अलग-अलग चरणों से गुजरती हैंख़कभी तेजी से बढ़ती हैं और कभी एक स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाती हैं। मिड कैप कंपनियां उस बीच के चरण में होती हैं, जहां उन्होंने छोटे बिजनेस वाली शुरुआती मुश्किलें जैसे पैसे जुटाना और शुरुआती ग्रोथ संभालना पार कर लिया होता है। अब ये कंपनियां मजबूत हो चुकी होती हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ बना लेती हैं और आगे बढ़ने की क्षमता रखती हैं। साथ ही, ये कंपनियां इतनी बड़ी भी नहीं होतीं कि उनकी ग्रोथ धीमी पड़ जाए। इसलिए मिड कैप कंपनियां एक अच्छा संतुलन देती हैंख़जहां छोटे बिजनेस की तेज ग्रोथ और बड़ी कंपनियों की स्थिरता दोनों का फायदा मिल सकता है। इस तरह कह सकते हैं कि मिड-कैप कंपनियां तेजी से बढ़ती छोटी कंपनियों और अच्छी तरह स्थापित बड़ी कंपनियों के बीच एक संतुलित और आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मिडकैप स्टॉक्स, लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच आते हैं और आमतौर पर कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तय किए जाते हैं। सेबी की परिभाषा के अनुसार, फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 101वें से 250 वें स्थान पर आने वाली कंपनियों को मिड कैप स्टॉक्स माना जाता है। एक मिडकैप फंड अपने फंड कॉर्पस का कम से कम 65 प्रतिशत हिस्सा मिडकैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित साधनों में निवेश करता है। मिडकैप कंपनियों में निवेश करने वाले फंड निवेशकों को मध्यम आकार के व्यवसायों की विकास कहानियों का लाभ उठाने का अवसर देते हैं। हालांकि, निवेशकों को यह समझना चाहिए कि इनमें जोखिम और रिटर्न की संभावना दोनों ही, अच्छी तरह विविधीकृत ग्रोथ फंड्स की तुलना में ज्यादा होती है।

यूटीआई मिड कैप फंड मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। फंड की रणनीति स्केलेबल बिजनेस मॉडल और लॉन्ग ग्रोथ रनवे के साथ कंपनियों में निवेश करने पर केंद्रित है, फंड उन अच्छी कंपनियों में भी निवेश करने के लिए खुला है, जिनका कारोबार कमजोरी के क्षणिक दौर से गुजर रहा है या परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

फंड पूरी तरह बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाकर उन कंपनियों का चयन करता है, जिनके पास बेहतर वित्तीय स्थिति और मार्जिन बनाए रखने की क्षमता हो। लगभग 90 शेयरों के विविधीकृत पोर्टफोलियो के साथ, यह विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों को कवर करता है। 7 अप्रैल 2004 को शुरू हुआ यह फंड, 30 नवम्बर 2025 तक 12,000 करोड़ से अधिक एयूएम के साथ, हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 85-90 प्रतिशत हिस्सा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में 72 प्रतिशत निवेश मिड कैप, 20 प्रतिशत स्मॉल कैप और शेष लार्ज कैप कंपनियों में है।

इसकी शीर्ष होल्डिंग्स में पॉलिकैब इंडिया, फीनिक्स मिल्स लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, अजंता फार्मा लिमिटेड और ट्यूब इंवेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं, जो कुल पोर्टफोलियो का लगभग 22 प्रतिशत हैं। अपने विविध प्रदर्शन के साथ फंड का उद्देश्य पोर्टफोलियो में कंपनियों के प्रति एक धैर्यशील दृष्टिकोण और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड (आरओसीई) और कैश फ्लो प्रोफाइल के साथ कंपनियों के सही मिश्रण से रिस्क और रिवार्ड के बीच संतुलन बनाना है। इससे पोर्टफोलियो के तेज रिटर्न डाइवर्जेंस और अस्थिरता को कम करने में मदद मिलेगी। रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में यूटीआई का समृद्ध अनुभव, मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में कंपनियों के बड़े क्रॉस सेक्शन के कवरेज से मिलकर फंड को गुणवत्ता वाले शेयरों को चुनने में मदद करेगा और कमजोर शेयरों से भी बचना होगा। यूटीआई मिड कैप फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं और अपनी अंतर्निहित विकास क्षमता के साथ अपने मुख्य इक्विटी पोर्टफोलियो के पूरक के लिए निवेश कर रहे हैं। इस फंड की शुरुआत 7 अप्रैल, 2004 को हुई थी और 31 मार्च, 2026 तक इसकी कुल प्रबंधित संपत्ति (एयूएम)10,480 करोड़ से अधिक है। यह फंड अपनी श्रेणी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए यह हर समय पोर्टफोलियो का 85-90 प्रतिशत हिस्सा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में रखना पसंद करता है। 31 मार्च, 2026 तक, फंड का लगभग 69 प्रतिशत निवेश मिड कैप में, 21 प्रतिशत स्मॉल कैप में और शेष लार्ज कैप कंपनियों में है।

फंड की शीर्ष होल्डिंग्स में मुख्य रूप से निम्नलिखित कंपनियां शामिल हैं जो पोर्टफोलियो का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं: पीबी फिनटेक लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, अजंता फार्मा लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड और ब्लू स्टार लिमिटेड। यह फंड जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है और इसके लिए यह मजबूत रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अच्छे कैश फ्लो वाली कंपनियों पर ध्यान देता है।

इस तरह का चयन पोर्टफोलियो में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकता है। रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में यूटीआई का लंबे अनुभव का लाभ भी इस फंड को मिलता है, जिससे यह अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों को चुनने और कमजोर कंपनियों से बचने की कोशिश करता है। यूटीआई मिड कैप फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त माना जा सकता है जो अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में मिड कैप कंपनियों के जरिए अतिरिक्त ग्रोथ जोड़ना चाहते हैं, थोड़े अधिक जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न की संभावना तलाश रहे हैं और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने के लिए तैयार हैं।